THE

PARLIAMENTARY DEBATES

OFFICIAL REPORT

IN THE NINETY-FOURTH SESSION OF THE RAJYA SABHA

Commencing on the 5th January/1976, the 15th Pausa, 1897 (Saka)

RAJYA SABHA

Monday, the 5th January, 1976, *the* 15*th Pausa,* 1897 (*Saka*)

The House met at fifteen minutes past twelve of the clock, MR. CHAIRMAN in the Chair.

MEMBERS SWORN

1. Shri Hari singh Bhagubava Mahida (Gujarat)
2. Shri Ramlal D. Parikh (Gujarat)
3. Shri Zawar Husain (Bihar)
4. Shri Viren J. Shah (Gujarat)
5. Shri Leonard Solomon Saring (Sikkim).

PRESIDENT'S ADDRESS

SECRETARY GENERAL: Sir, I beg to lay on the Table a copy (in English and Hindi) of the President's Address to both the Houses of Parliament assembled together on the 5th January, 1976.

(*Text of the President's Address in Hindi*)

मैं बहुत खुशी से आप सब का स्वागत करता हूं, खास कर सिक्किम के नुमाइन्दों का जो मई 1975 में भारतीय यूनियन का 22वां राज्य बना । सरकार की यह कोशिश होगी कि इस पिछड़े पहाड़ी राज्य का तेजी से विकास हो ।

860 RS—20.

पिछले साल, सरकार की मजबूत कार्रवाई की वजह से अर्थ-व्यवस्था में अच्छे नतीजों का जिक्र करते हुए मैंने आपका ध्यान कुछ जमातों की उन कोशिशों की तरफ भी दिलाया था जो मोजुदा निज़ाम और संस्थाओं को छिन्न-भिन्न करना चाहती थी जिससे देश की तरक्की और पायदारी ख़तरे में पड गयी थी । मैंने उनसे अपील की थी कि तबदीलियां लाने के लिए वे बातचीत का रास्ता अपनायें और सुधार के लिए तजवीजों का स्वागत किया था । मुझे अफसोस है कि इस अपील पर कोई तवज्जो न दी गई । कुछ जमातें और ऐसे लोग, जिनके विचार एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, देश के आर्थिक और राजनीतिक जीवन में रुकावट डालने के लिए आपस में मिल गए । उन्होंने लोगों के मन में गलतफहमी पैदा करने और बदअमनी फैलाने के लिए हर मौके का गलत फायदा उठाना चाहा । उनकी इन कार्रवाइयों से देश की अन्दरूनी सलामति बड़े खतरे में पड गई थी । उनका यह मकसद था कि किस तरह आर्थिक अपराध रोकने, पैदावार बढ़ाने और बढती हुई इन्फ्लेशन पर काबू पाने, माल को सही ढंग और तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने, अर्थ-व्यवस्था को पायेदार बनाने और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार की जोरदार कोशिशों को नाकाम बनाया जाये । देश के हित में कड़ा और फैसलाकुन कदम उठाना लाज़मी हुआ ।

25 जून, 1975 के एमरजेंसी के एलान, 1 जुलाई, 1975 को 20 सूत्री आर्थिक प्रोग्राम की घोषणा और कौमी जिन्दगी के सभी क्षेत्रों में कार्यकुशलता बढ़ाने के लिये उठाये गए कदमों से राष्ट्र के जीवन पर नुमायां असर पड़ा। मायूसी और बे-हिसी की जगह जो एतमाद पैदा हुआ उससे हमें महसूस हुआ कि अगर हममें एकता और डिसिप्लिन हो और अपनी शक्ति को जाया न होने दें तो हम अपनी समस्याओं को कामयाबी से हल कर सकते हैं। जनता ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की भरपूर ताईद की है और देश की फिज़ा में आई हुई तबदीली का स्वागत किया है। इससे उत्साहित होकर सरकार ने बहुत से मामलों में फैसलाकुन कार्रवाई की है। इन्फ्लेशन पर काबू पा लिया गया है। सितम्बर 1974 में बहुत बढ़ी हुई कीमतों के मुकाबले में अब औसतन दस फी सदी गिरावट आई है और खाने पीने की चीजों की कीमतों में तकरीबन 20 फी सदी कमी हुई है। आर्थिक अपराधों के खिलाफ, कड़ी कार्रवाई की गयी। 1973 में और 1974 के शुरू में कोयला, बिजली, इस्पात और सीमेंट जैसी चीज़ों की कमी और ट्रांसपोर्ट सिस्टम में गडबड़ी और खराब कार कर्दगी से हमारी अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुचा था। इस साल उत्पादन बढा है और इन सभी क्षेत्रों के काम में नुमायां सुधार हुआ है। मज़दूरों के सहयोग से कुछ को छोड़कर, सभी उद्योगों में शान्ति रही है। हमारी इक्तसादी हालत में जो बहुत से डिस्टार्शन्ज़ और इम्बैलेसिज पैदा हो गए थे उनमें सुधार हुआ है। इसकी वजह से कुछ तबकों के जो विशेषाधिकार थे उनमें कमी हुई है। लेकिन यह याद रखना चाहिए कि कोई भी तबका अलग रह कर सिर्फ अपने ही हितों को नहीं बढ़ा सकता। हर एक तबके की भलाई का दारोमदार मजमुई इक्तसादी मजबूती पर ही है।

गरीबों की बहबूदी के प्रोग्रामों में एक नई जान डाली गयी है। जिन लोगों के पास जमीन नहीं है उन्हें घर बनाने के लिये जमीन दिलाने, भूमि सुधार लागू करने खेती बाड़ी पर काम करने वालों को मजदूरी बढ़ाने और कर्जे से राहत दिलाने के काम तेजी से आगे बढ़ाये जा रहे हैं।

गरीबी का हल थोड़े अर्से में नही निकाला जा सकता। लगातार कड़ी मेहनत और जिन्दगी के सभी शोबों में डिसिप्लिन से ही इसमें तबदीली लायी जा सकती है। इसलिए पिछले महीनों में जो नया जोश पैदा हुआ है उसमे कमी नही आनी चाहिए और उसे जारी रखना है।

20 सूत्री आर्थिक प्रोग्राम पर पूरी लगन से अमल किया जायेगा। सरकार जनता का पूरा सहयोग चाहती है, क्योंकि यह जनता का प्रोग्राम है और इसे सिर्फ सरकारी एजेंसियों से ही नहीं चलाया जा सकता।

इस साल जैसी खरीफ की फसल पहले कभी नहीं हुई। अनाज की ज्यादा से ज्यादा वसूली की जाएगी ताकि किसान प्रोक्योर्मेंट प्राईस से कम पर अनाज बेचने पर मजबूर न हो और साथ ही साथ नागहानी जरूरत के लिये हमारे पास काफी स्टाक हो।

हम चाहते है कि 1979 के पहले ही और 50 लाख हैक्टेयर की सिंचाई का इन्तजाम हो सके। राज्यों के आपसी झगड़ों की वजह से कई प्रोजेक्टों को शुरू करने में देरी हुई है। सरकार इस उसूल को मनवाने की कोशिश करेगी कि पानी राष्ट्रीय सम्पत्ति है जिसका इस्तेमाल देश के बेहतरीन फायदे के लिये होना चाहिए। नदी घाटियों के मास्टर प्लान को तैयार करने के लिये एक नैशनल वाटर रिसोर्सिज़ कौंसिल काफी इख्तयारात के साथ कायम की जाएगी। इस अर्से में, संबंधित राज्यों को एक साथ ला करके ज्यादा से ज्यादा

झगड़ों को तय करने की तेज़ी से कोशिश की जा रही है। इसी कोशिश का नतीजा है कि नर्मदा घाटी के कुछ प्रोजेक्ट, बेतवा नदी पर राजघाट प्रोजेक्ट और माही नदी पर कडाना प्रोजेक्ट के संबंध में समझौते हो गए हैं। हाल ही में, गोदावरी नदी के पानी के अधिक भाग के इस्तेमाल के संबंध में पाच राज्यों के बीच हुआ समझौता, राज्यों के दम्यान पानी के झगड़ों को बातचीत के जरिये हल करने की दिशा मे एक अहम कदम है। गोदावरी घाटी देश के रकबे का दसवा हिस्सा है और इस समझौते से पचास लाख हैक्टर जमीन की सिचाई करने के प्रोजेक्ट बनाने में मदद मिलेगी।

इस साल सालाना योजना के लिये पिछले साल के मुकाबले मे 25 फी सदी ज्यादा का प्रावधान है। प्राथमिक क्षेत्रों पर जोर का ध्यान देते हुए इसे अगले साल और बढ़ाया जायेगा ताकि विकास की तहरीक मे और तेजी आये। साथ ही साथ कपड़े और चीनी जैसे उद्योगों को, जो जनता की आम जरूरतों को पूरा करते है और जिनकी मशीनें पुरानी हो चुकी है, जदीद बनाने के लिए कदम उठाये जायेंगे।

सनअती लाईसैंसिंग की पालिसी और उसके काम करने के तरीकों पर फिर से गौर किया जा रहा है। आर्थिक शक्ति को कुछ ही हाथों मे जमा होने पर रोक-थाम लगाने की नीति का पालन करते हुए, प्राथमिक क्षेत्रों मे उत्पादन बढाने और नई सनअतों को बढावा देने की खातिर ऐसे कन्ट्रोल हटा दिये जायेगे जिनकी अब जरूरत नही है।

पिछले 3 सालों की अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाओं की वजह से हमारे बैलस आफ पेमेंट्स पर भारी बोझ पड़ा है। इक्तसादी हालत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निर्यात मे काफी इजाफा जरूरी है। निर्यात बढाने के लिये हाल ही में कई कदम उठाये गए हैं। हैंडलूम और दस्तकारी की चीजों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकारों की मदद से खास कदम उठाए जायेंगे। रुकावटों और कमियों को दूर करने के लिये नीति और काम के तरीकों पर गौर किया जा रहा है।

इन्तजामी कार्यकुशलता को बेहतर बनाने की कोशिशों को जारी रखा जायेगा और इन्हें बढ़ाया जायेगा। हमारे इन्तजाम के तरीकों और नजरियों मे ज्यादा तबदीली नही हुई है, खास तौर से माली इन्तजाम मे, जिसका असर सरकार के सभी क्षेत्रों की कार-कर्दगी पर पड़ता है। सरकार ने माली इन्तजाम में सुधार लाने की एक मुकम्मिल योजना तैयार करने का फैसला किया है, जिस पर इस साल मे अमल होगा। यूनियन का हिसाब-किताब आडिट से अलग करके डिपार्टमैंट्स के सुपुर्द कर दिया जाएगा। तनख्वाह और पैन्शन की अदायगी, प्रोविडेंट फड का हिसाब-किताब, रुपया जमा करने, निकालने और खर्च की मंजूरी के नियम और तरीकों को आसान और जदीद बनाया जाएगा। कर्मचारियों के काम करने के तरीकों का जायजा लेने के ढग को बदलना होगा ताकि हर सतह पर एडमिनिस्ट्रेशन अपनी कार कर्दगी के बारे मे जवाबदेह और रिजल्ट-ओरिएंटिड हो।

चेचक का जड़ से दूर कर देना सेहत के क्षेत्र मे एक बड़ी कामयाबी है। यह वबा दोबारा न हो, इसके लिए बड़ी निगरानी रखी जा रही है। छूत की दूसरी बिमारियों के खिलाफ भी मुहिम तेज की जा रही है।

हम कोशिश कर रहे है कि अगले तीन सालों मे जन्म दर घट कर 30 फी हजार आ जाय। इस मकसद को हासिल करने के लिए, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को जन-आन्दोलन का रूप लेना होगा। इन्सेंटिव और डिसइन्सेंटिव की नई स्कीमें

तैयार की जा रही हैं, ताकि छोटे परिवार की मकबूलियत में इजाफा हो ।

दूसरे देशों की तरह हमने भी 1975 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया । बहुत से क्षेत्रों में महिलाओं के मामलों का तफसील से अध्ययन किया गया है । महिलाओं को बराबर काम के लिए बराबर उजरत दिलाने का आर्डिनेंन्स इस सेशन मे आपके सामने आएगा । महिलाओं के लिए एक राष्ट्रीय योजना तैयार की जा रही है, जिसके अमल से उन कमियों को दूर करने में मदद मिलेगी जिनकी वे शिकार हैं ।

पहले सेटलाईट "आर्यभट्ट" के निर्माण पर स्पेस साईटिस्ट्स और इन्जीनियर्स को मैं बधाई देता हूं । देहात की जनता के हित में साइन्स और टैक्नालोजी को अमली तौर से इस्तेमाल मे लाने के लिए सेटलाईट इंस्ट्रक्शनल टेलिविजन एक्सपैरीमेंट की कायमयाबी एक नुमायां कदम है । इस तजुर्बे से हम टेलिविजन को गांव में जन-सम्पर्क के साधन के रूप में इस्तेमाल करने के बारे मे तय कर सकेंगे।

अनर्जी के नए जरियों के विकास की अहमियत को मान लिया गया है और कई क्षेत्रों मे काम को तेज किया जा रहा है । बायो-गैस और सोलर अनर्जी के इस्तेमाल को ज्यादा तरजीह दी जा रही है ।

अब मैं दूसरे देशों के साथ अपने सम्बन्धों के बारे मे जिक्र करूंगा ।

हमारा यह पक्का विश्वास है कि इस उप-महाद्वीप के सभी देशों मे सामान्य और दोस्ती के तालुकात अवाम की तरक्की के लिए जरूरी है ।

बंगलादेश मे हाल की घटनाओं से हमें दुःख और चिन्ता हुई । शेख मुजीबुर्रहमान, उनके परिवार और साथियों की बेरहमी से हत्या का हमें बड़ा दुःख और गहरा सदमा पहुंचा । फिर भी, हमने बंगलादेश की घटनाओं को उस देश का अन्दरूनी मामला समझा । इसलिए, कुछ हल्कों में, जो गलत प्रचार किया जा रहा है, उससे हमें बहुत दुःख है । दोनों देशों के नुमाइन्दों के बीच हाल की बातचीत में हमने इस बात पर फिर जोर दिया है कि हम सीमा पर शांति चाहते हैं और यह भी कि बंगलादेश पायेदार और स्वतंत्र रहे जहां सभी तबके के लोगों के हित और कल्याण की रक्षा हो सके । बंगला देश ने अपनी नीति बनाये रखने और अपनी जनता को, चाहे किसी भी जाति, मजहब या धर्म से ताल्लुक रखती हो, समान अधिकार देने की ख्वाहिश पर जोर दिया है ।

मुझे दुःख है कि शिमला समझौते पर अमल की रफ्तार धीमी रही है, क्योंकि पाकिस्तान का रवैया निराशाजनक रहा है जो कि भारत की गलत तस्वीर पेश करने की अपनी मुहिम जारी रखे हुए है ।

भूटान के साथ दोस्ती के हमारे पुराने सम्बन्ध और बढ़ रहे है और मजबूत हो रहे है । चूखा पनबिजली प्रोजेक्ट का काम शुरू होने से आर्थिक सहयोग का प्रोग्राम बहुत आगे बढ़ा है ।

1975 मे नेपाल के महामहिम नरेश और महारानी की भारत यात्रा से उस मित्र पड़ौसी देशके साथ हमारे सम्बन्ध और मजबूत हुए । उनकी यात्रा के दौरान जो बातचीत हुई, उस का नतीजा यह निकला कि नेपाल से भारत मे बहने वाली नदियों के पानी के इस्तेमाल के बारे मे बाहमी फायदों का बेहतर अन्दाजा हुआ है ।

श्री लंका के साथ हमने अनौपचारिक बातचीत और आपसी हित के मामलों मे

सहयोग की परम्परा को और मजबूत किया है। बर्मा के साथ हमने अपने आर्थिक, सांस्कृतिक और विज्ञान सम्बन्धी ताल्लुकात बढ़ाये हैं।

हमने दक्षिण पूर्व एशिया तथा जापान और पूर्व एशिया के दूसरे देशों के साथ अपने सम्बन्धों को मजबूत करने की कोशिश की। हिन्द-चीन में बहुत दिनों से चली आ रही लड़ाई खत्म होने पर हमें खुशी हुई और हमने उस समझौते का स्वागत किया, जिसके मुताबिक वियतनाम के दोनों इलाके फिर से एक दूसरे से मिल गये। हमारा विश्वास है कि री-युनाईटिड वियतनाम और पायेदार और आर्थिक लिहाज से मजबूत कम्बोडिया और लाओस दक्षिण पूर्व एशिया में शांति और इस्तेहकाम का बाईस होंगे। मैंने मार्च, 1975 में इन्डोनेशिया की यात्रा की, और पाया कि इन्डोनेशिया और भारत के बीच आपसी हित के आर्थिक, सनअती और तकनीकी सहयोग के फायदे का अहसास बढ़ रहा है।

तारीखी और सांस्कृतिक समानता और मौजूदा मसलों पर एक जैसे नजरिये के आधार पर अफगानिस्तान के साथ हमारे करीबी और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। हमें खुशी है कि टैक्नीकल और आर्थिक सहयोग के प्रोग्राम में अच्छी तरक्की हो रही है।

ईरान के साथ एक दूसरे के नजरिये को बेहतर समझने और आपसी हित के मामलों में हमारे आदान प्रदान बढ़े और फैले। खुदरेमुख आयरन और प्रोजेक्ट के विकास के लिये समझौते पर दस्तखत होना इस सिलसिले में एक नुमायां कदम है।

अरब देशों के साथ आर्थिक, तिजारती और सांस्कृतिक सम्बन्ध बढ़ रहे हैं। मिस्र अरब गणराज्य और सूडान यात्रा से मुझे पश्चिम एशिया की समस्याओं को और गहराई से समझने का मौका मिला। सरकार अपने इस विश्वास पर फिर जोर देती है कि जब तक ताकत के जोर से कब्जा की हुई अरबों की जमीन को खाली नहीं किया जाता और फिलिस्तीनियों को उनके जाइज हक वापिस नहीं दिये जाते, तब तक पश्चिम एशिया में पायेदार अमन कायम नहीं हो सकता।

मोजम्बिक, अंगोला, केप वर्डे, सन तोमे और प्रिंसिपे को सदियों पुरानी पुर्तगाली कलोनियलिज्म से आजादी हासिल करने पर बधाई देते हैं। साथ ही कमोरोस, सूरीनाम और पपुआ न्यू गिनि के स्वतंत्र होने का हम स्वागत करते हैं।

हम अंगोला के अन्दरूनी मामलों में दक्षिण अफ्रीका की हथियारबन्द मदाखलत की निन्दा करते हैं। भारत ने अफ्रीका एकता संगठन का बराबर समर्थन किया है और अपार्थाइड को खत्म करने, नमीबीया को आजाद कराने, जिम्बाबवे और दक्षिण अफ्रीका में माईनोरेटी रूल खत्म करने की सभी कोशिशों में भारत अफ्रीका का साथ देगा।

सोवियत संघ तथा पूर्वी यूरोप के देशों के साथ भारत के सम्बन्ध गहरी दोस्ती, समझबूझ और बढ़ते हुए क्षेत्रों में आपसी हित में सहयोग की बुनियाद पर कायम है। इन देशों ने सभी अहम मामलों में भारत का हमेशा समर्थन किया है। पिछले महीनों में कई बड़े नुमाइन्दे एक दूसरे के देश गये और मैंने हंगरी और यूगोस्लाविया की यात्रा की।

यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन की कामयाबी पायेदार शांति की तरफ एक अहम कदम है। तनाव कम करने की यह भावना दुनिया के उन देशों में भी फैलनी चाहिए जहां झगड़ा और तनाव अब भी है। ई०ई०सी० और पश्चिम यूरोप के दूसरे देशों के साथ व्यापार और साइंस टैक्नोलोजी के क्षेत्रों में हमारे आर्थिक सहयोग और सम्बन्ध बढ़ रहे हैं।

हम चाहते है कि यू० एस० ए० के साथ हमारे सम्बन्ध पक्के और अमल पजीर हों। शांति, पायेदारी और सहयोग को मजबूत बनाने के लिए एक दूसरे के विचारों को समझने की पूरी कोशिश की जानी चाहिए।

नान-एलाइन्ड देशों के राज्याध्यक्षों का अगला सम्मेलन इस साल अगस्त में श्रीलका में होगा। हमें खुशी है कि नान-एलाइन्मेंट को व्यापक रूप से मान्यता मिली है। लेकिन साथ कुछ ऐसी कोशिशे भी की जा रही है कि नानइलान्ड मुवमेंट कमजोर और धीमी हो। हम गुटों से दूर रहने के बुनियादी उसूलों और नान एलाइन्ड देशों की एकता और प्रभाव बनाये रखने के लिये कोशिशे करते रहेंगे।

दुनिया की अर्थव्यवस्था की सब से खटकने वाली बात यह है कि इस पर कुछ अमीर देश हावी हैं और सारा बोझ गरीब और विकासशील देशों को सहना पड़ता है। ज्यों ज्यों समय गुजरता है, इन देशों की समस्यायें और भी कठिन होती जा रही हैं। इस रुख को जल्दी बदलना होगा और ऐ उपाय करने होंगे जिन से दुनिया में एक नयी अर्थव्यवस्था कायम हो सके। यू० एन० जनरल असेम्बली के सातवें विशेष अधिवेशन में सबका इत्तेफाक राय होना आपसी बातचीत की शुरुआत में एक कदम है। अनर्जी, कच्चे माल और सनअती पैदावार की कीमते मुकर्रर करने के लिये और गरीब देशों के आर्थिक विकास की समस्याओं का उचित हल निकालने की गरज से हमने अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग पर पैरिस सम्मेलन मे तामीरी हिस्सा लिया। हमें उम्मीद है कि सभी सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय मंचों मे कार्रवाई के लिए जल्द से जल्द ठोस समझौते हो जायेगे।

माननीय सदस्यगण, अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति मे, खास कर हमारे सब-कांटिनेंट और पड़ौसी देशों मे गैर यकीनी हालत का होना देश में विघटनकारी शक्तियों की चुनौती का जारी रहना और सामाजिक और आर्थिक प्रोग्रामों को तेज करने की जरूरत मानते हुए राष्ट्र को चौकस और अनुशासित रहना होगा। कार्य कुशलता बढ़ाने और राष्ट्रीय जीवन के हर क्षेत्र मे तब्दीली और सुधार लाने की लगातार कोशिश जारी रहनी चाहिये।

खत्म करने से पहले मै चाहता हूं कि चासनाला कोयला खान के दर्दनाक वाकया, जिसकी मिसाल नहीं मिलती, का जिक्र करूं जिससे सारे देश मे गहरा रंज छा गया ह। खान से पानी निकालने का काम जारी है। बहुत से दोस्त मुल्क और देश मे कई संस्थायें इस काम में मदद पहुंचाने के लिए आगे आइ। जिन परिवारों पर इस दुर्घटना से सम्बन्धित मुसीबते आई हैं उनकी तकलीफें दूर करने और खान मजदूरों की सुरक्षा के इन्तजाम में सुधार लाने के लिये सरकार कोई दकीका बाकी न रखेगी।

आपका यह अधिवेशन मुखतसर होगा, लेकिन इसका एजेंन्डा भारी है। पिछले सेशन के बकाया मामलों तथा आर्डिनेंसों को पालिया-मेंट के एक्टों मे बदलने के अलावा आपको इस अधिवेशन में पेश किये जाने वाले अर्बन लैंड सम्बन्धी बिल पर विचार करना है। ऐसा वक्त है कि एक मिनट भी जाया नहीं किया जा सकता। मुझे यकीन है कि आप साफ, साहसपूर्ण और मजबूत रहनुमाई करेंगे, जिसकी जनता आपसे आशा रखती है। मैं आपको इन अहम कामों को शुरू करने की दावत देता हूं और आपकी सफलता की कामना करता हूं।

जय हिन्द।

(Text of the President's address in English)

It gives me great pleasure to welcome you all and particularly to have in our midst the representatives of Sikkim, which became the 22nd State of the Indian Union in May, 1975. It will be the endeavour of Government to ensure speedy development of this neglected hill State.

Last year, while noting the positive trends in the economy arising out of the firm measures taken by Government, I drew attention to the efforts of some groups to disrupt the existing system and institutions and the danger this posed to the stability and progress of our country. I appealed to them to follow the path of discussion to bring about changes and welcomed suggestions for reform It is most unfortunate that this appeal was not heeded. Groups and elements of widely differing persuasions joined together to paralyse the country's economic and political life. They clutched at every opportunity to create confusion in the minds of the people and to foment chaos and disorder. Their activities seriously threatened internal security. They were directed towards undermining Government's vigorous efforts to curb economic offences, increase production and ensure the smooth and speedy movement of goods in order to stem the rising tide of inflation, stabilise the economy and bring relief to the people. The nation's interests demanded firm and decisive action.

The declaration of emergency on June 25, 1975, the 20-point Economic Programme launched on July 1, 1975 and the steps taken to tone up efficiency in all spheres of national life have had a dramatic effect on the health of the nation. Diffidence and apathy have given place to confidence that we can face our problems successfully if we are disciplined and united, and do not allow our energies to be frittered away. Our people have given overwhelming support to the steps taken by the Government and have welcomed the change in the atmosphere in the country Strengthened by this, decisive action has been taken by Government on a wide front. Inflation has been checked. The overall price level has come down by 10 per cent when compared to the peak level reached in September, 1974, the fall in the price level of food articles being nearly 20 per cent. Stringent action has been taken against economic offences. Shortage of coal, power, intermediate goods like steel and cement and the dislocation and inefficient working of the transport system had severely strained the economy during 1973 and early 1974. This year production has increased and performance improved significantly in all these sectors. With the co-operation of workers, industrial peace has been maintained, save in a few isolated cases. Several distortions and imbalances that had developed in the economy have been corrected. As a result of this, the privileges enjoyed by some groups have been reduced. But it should be remembered that no single group can further its interests in isolation. The interests of each group are dependent on the soundness of the economy as a whole.

New vigour has been imparted to the implementation of programmes for the uplift of the poor. Rapid progress is being made in allotment of house sites to the landless, implementation of land reforms, increasing agricultural wages and giving relief from debts.

The problem of poverty cannot be solved in a short time. We can make a dent in it only through sustained hard work and discipline in all walks of life. The new spirit that has been generated over the last few months should therefore be maintained unimpaired.

The 20-point Economic Programme will continue to be implemented with zeal. Government invites the full co-operation of the people as it is a peoples' programme and cannot be implemented by official agencies along.

We have a record kharif crop this year. The maximum quantity of grain will be procured so that farmers will not have to sell below the procurement price and in order to have sufficient stocks to meet any unforeseen eventuality.

We aim to extend irrigation to five million more hectares before 1979. Disputes between States have delayed a number of projects. Government will try to get acceptance of the concept of water as a national asset to be utilised to the best advantage of all the people. A National Water Resources Council with adequate powers to prepare master plans for river basins will be constituted. Meanwhile, efforts have been intensified to settle as many disputes as possible by bringing the concerned States together. As a result, agreements have been reached regarding some projects in the Narmada basin, the Rajghat project on the Betwa river and the Kadana project on the Mahi river. The recent agreement amongst five States on the utilisation of a major portion of the waters of the Godavari river is a landmark in the settlement of inter-State water dispute by negotiations. The Godavari basin covers a tenth of the area of the country and the agreement will enable the construction of projects to irrigate five million hectares of land.

The outlay on the annual plan this year is 25 per cent higher than last year's. This will be further increased next year with emphasis on priority sectors so that the impulses of growth are quickened. Simultaneously, steps will be taken to ensure the modernisation of industries like textiles and sugar, which are engaged in the production of mass consumption goods and have been suffering from obsolescence and sickness

Industrial licensing policies and procedures have been under review. Controls which are no longer relevant will be removed to increase production in priority areas and widen the entrepreneurial base, consistent with the objective of curbing the concentration of economic power.

International economic events of the last three years have imposed severe strain on our balance of payments. A big increase in exports is essential to achieve a self-reliant economy. Several measures have recently been initiated to promote exports. Special steps will be taken, with the assistance of State Governments, to increase exports of handlooms and handicrafts. A review of policies and procedures is being made so as to remove constraints and obstructions.

Measures to improve administrative efficiency will continue and will be expanded. Our administrative procedures and attitudes have remained largely unchanged, specially in the field of financial administration which affects the working of all wings of Government Government has decided upon a comprehensive scheme of reform of financial administration, which will be put through this year. The maintenance of accounts of the Union will be departmentalised and separated from Audit. Rules and producers for payment of salaries and pensions, maintenance of provident fund accounts, remittance and withdrawal of moneys, and for sanction of expenditure will be simplified and modernised. Methods of evaluation of performance will have to be changed in order to make the administration at every level result-oriented and accountable.

A major achievement in the field of health is the eradication of small pox. Strict vigil is being kept against the recurrence of this scourge. The campaign against other communicable diseases is being intensified.

We are aiming to reduce the birth rate to 30 per thousand in the next three years. To achieve this, the family planning programme will have to become a mass movement New schemes of incentives and disincentives are being evolved to increase the acceptance of a small family.

Along with other countries, we observed 1975 as International Women's Year. The problems faced by women in a number of areas have been studied in detail. The Ordinance guaranteeing to women equal remuneration for equal work will come before you this session. A National Plan for Women is being prepared, the implementation of which will help to remove some disabilities from which they suffer.

I congratulate our Space Scientists and Engineers on the construction of our first Satellite, Aryabhata. The successful working of the Satellite Instructional Television Experiment is a landmark in the practical application of science and technology for the benefit of the rural population. This Experiment will help us to decide on the use of television as a means of mass communication in rural areas.

The importance of developing new sources of energy has been recognised and work is being intensified in a number of areas. Bio-gas plants and the utilisation of solar energy are being given high priority.

I shall now deal with our relations with other countries.

We remain firm in our conviction that normal and friendly relations between all the countries of the sub-continent are essential for the progress of their peoples.

Recent events in Bangladesh have caused us anguish and concern. We were shocked and grieved by the brutal assassination of Sheikh Mujibur Rahman, the members of his family and his associates. Nevertheless, we have treated developments in Bangladesh entirely as an internal affair of that country. We are therefore distressed by the false propaganda that is being carried on in some quarters. In recent talks between representatives of the two countries, we have reaffirmed our desire for a peaceful border and a stable, strong and independent Bangladesh in which the interest and welfare of all sections of its people are safeguarded. Bangladesh emphasised its desire to continue the policy and ensuring equal rights to all its people, irrespective of caste, creed and religion.

I regret that the progress of implementation of the Simla Agreement has been slow because of disappointing response from Pakistan, which has continued a campaign of misrepresentation of India.

Our traditional bonds of friendship with Bhutan are growing. The programme of economic co-operation has taken a giant stride with the starting of work on the Chukha hydro-electric project.

Relations with our friendly neighbour, Nepal, were further strengthened by the visit to India of their Majesties the King and Queen in 1975. As a result of the discussions held during the visit, there is better appreciation of the mutual advantages of a joint approach to the utilisation of waters of the rivers flowing into India from Nepal.

With Sri Lanka we have strengthened the tradition of informal and mutually beneficial exchanges and collaboration on matters of common interest. We have improved our economic, cultural and scientific links with Burma.

We have sought to strengthen our relations with our neighbours in South-East Asia as well as with Japan and other countries of East Asia. We rejoiced at the ending of the prolonged hostilities in Indo-China and have welcomed the negotiations leading to the reunification of the two Zones of Vietnam. We believe that a reunited Vietnam and stable and economically strong Cambodia and Laos will constitute forces for peace and stability in South-East Asia. I visited Indonesia in March, 1975, where I found a growing awareness of the possibilities and mutual advantages of increased economic, industrial and technological

co-operation between Indonesia and India.

We have close and friendly ties with Afghanistan, based on historical and cultural affinity and on similarity of approach to current problems. We are gratified that programmes of technical and economic co-operation are making good progress.

Our understanding and mutually beneficial exchanges with Iran have grown and become more varied. An important landmark in this process has been the signing of agreements for the development of the Kudremukh Iron Ore Project.

Economic, commercial and cultural contacts with the Arab countries continued to make progress. My visit to the Arab Republic of Egypt and the Sudan gave me deeper insight into the problems of West Asia Government reaffirms its belief that lasting peace in West Asia will not be achieved untill Arab territories seized by force are speedily vacated and the legitimate rights of the Palestinian people restored.

We greet Mozambique, Angola, Cape Verde, Sao Tome and Principe on their achievement of independence from centuries of Portuguese colonialism. We also welcome the emergence to independence of Comoros, Surinam and Papua New Guinea.

We cannot but condemn armed intervention by South Africa in the internal affairs of Angola. India has steadfastly supported the organisation of African unity and will join with Africa in all measures to end apartheid, to liberate Namibia and to end racist minority rule in Zimbawe and South Africa.

India's relations with the Soviet Union and countries in Eastern Europe are characterised by a spirit of warm friendship, understanding and mutually beneficial co-operation in a widening variety of fields. These countries have consistently supported India on all issues of vital concern. In the last few months, a number of high level visits have been exchanged and I visited Hungary and Yugoslavia.

In Europe, the successful conclusion of the conference on Security and Co-operation marks an important step in the consolidation of peace. This spirit of detente should extend to other parts of the world where conflict and tension persist. Our economic co-operation as well as relations in the fields of trade and science and technology with the E.E.C. and other countries of Western Europe has continued to expand.

We desire a mature and constructive relationship with the United States of America A serious effort should be made to understand each other with a view to strengthening peace, stability and co-operation.

The next conference of Heads of State and Government of non-aligned countries will be held in Sri Lanka in August this year. We are glad that the validity of non-alignment has come to be recognised more widely. At the same time attempts are being made to weaken and dilute the non-aligned movement. We shall continue to strive to preserve the fundamental principles of non-alignment and the solidarity and effectiveness of non-aligned countries.

The most striking feature of the world economy is dominance by a small number of rich countries. The developing poor countries bear the brunt of the burden. As each year passes, the problems of these countries become more acute. This trend must be reversed urgently and steps taken to establish a new world economic order. The consensus reached at the seventh special session of the United Nations General Assembly marks the beginning of a dialogue. In the Paris Conference on International Economic Co-operation, we contributed constructively in an effort to evolve equitable solutions to the problems of energy,

the pricing of raw materials and industrial products and of the economic development of poor countries. We hope that concrete agreements for action will be reached in relevant international forums as early as possible.

Honourable Members, in view of the uncertainties of the international situation, especially on our sub-continent and the neighbourhood, the continuing challenge of forces of disruption at home and the need to accelerate our social and economic programmes, the nation should remain vigilant and disciplined. There must be constant effort to improve performance and bring about changes and reforms in every sphere of national life.

Before concluding, I should like to refer to the unprecedented tragedy in Chasnala Colliery, which has plunged the whole nation in deep sorrow. The work on clearing the mine of the flooded water is in progress. Several friendly countries and a number of organisations within the country have come forward to assist this operation. Government will spare no efforts to mitigate the sufferings of the affected families and to improve conditions of safety for workers.

Your present session will be a short one, but the agenda is heavy. In addition to pending business from the last session and the conversion of Ordinances into Acts of Parliament, you have to consider the bill on urban land, which will be introduced during the sesion. There is not a minute to waste. I am sure you will provide the clear, bold and firm lead which the people expect. I summon you to your labours and wish you all success. Jai Hind.

OBITUARY REFERENCES

MR. CHAIRMAN: I have to refer with profound sorrow to the passing away of Shri K. Kamaraj and three of our ex-Members—Dr. N. S. Hardiker, Shri Rama Bahadur Sinha and Shri B. Shiva Rao.

Shri Kumaraswami Kamaraj, a man of masses, was in rapport with the poor and down-trodden who understood him perfectly and whom he easily understood.

Born in 1908 at Virudhunagar, Shri Kamaraj had no advantages of birth, fortune or education, yet by dint of sacrifice and sincerity and through sheer organisational ability and sturdy commonsense he, while starting life as an ordinary soldier in the struggle for freedom, rose to the highest position in the Congress Party, in the administration and in national life. As a true Gandhian, his sphere of influence was not confined to his home State only, but was spread over the entire country. Starting his career as a freedom fighter with his participation in the Salt Satyagraha Movement, his deep involvement continued in the National Movements of 1932, 1941, 1942 and 1945. Such participations earned him imprisonment many a time and he remained in jail for several years. He became (1) a member of the Tamil Nadu Congress Executive Committee and the AICC in 1931; (2) Secretary, Tamil Nadu Congres Committee in 1935; (3) President, Tamil Nadu Congress Committee in 1939; (4) Member of the Congress Working Committee in 1959; and (5) President of the Indian National Congress from 1964 to 1968.

He was elected to the Madras Legislative Assembly in 1937 and re-elected in 1946, 1952, 1957 and 1962; and was the Chif Minister of Madras (now Tamil Nadu) from 1954 to 1963. He was a member of the Constituent Assembly, was elected to the Lok Sabha in 1969; re-elected in 1971 and was its Member till his death.

His demise has removed from our midst a remarkable personality who wielded considerable influence and commanded the respect of all sections. His death is a great loss to the nation.